



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनोखी धाम सेवा समिति द्वारा 10 जुलाई को पत्रकार कॉलोनी (मानसरोवर) के अनोखी धाम (श्री हनुमंत स्वरूप नीब करौरी महाराज) में आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विमोचन किया। इस दौरान अनोखी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद रहे।

भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े मेजा बाँध में 10 फीट पानी आया

भीलवाड़ा, 02 जुलाई, (निसं)। जिलेभर में बुधवार को कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर दिनभर जारी रहा।

शहर की निचली बस्तियों, अपडरब्रिज व बस स्टेण्ड मार्ग सहित कई मार्गों में पानी भरा होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। मांडल क्षेत्र के सबसे बड़े मेजा बांध में भी बारिश से पानी की आवक लगातार जारी है। भीलवाड़ा जिले के इस सबसे बड़े बांध में अब तक 10 फीट पानी पहुंच चुका है, बागीर क्षेत्र में सुबह से ही बारिश के कारण और अधिक पानी की आवक की संभावनाएं बताई जा रही है।

मानसून की पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम और यूआइटी की पोल खोलकर रख दी। भीलवाड़ा के कई इलाकों में तीन-तीन फीट पानी भर गया। दूसरी ओर मेजा बांध का जलस्तर बढ़ा है।

बारिश से पुलिस लाइन, यूआइटी के सामने, यातायात पुलिस चौकी, रामधाम के सामने, चन्द्रशेखर आजाद नगर सहित, शहर के सभी अपडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को चपटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। इस मौसम की पहली जोरदार बारिश से रोडवेज बस स्टेण्ड से रामस्नेही अस्पताल के बाहर तक तीन फीट पानी भर गया और बस स्टेण्ड के आस-पास बनी नालियों व नाले फोन कचरा सड़कों पर आ गया। नगर निगम के बाहर भी कई जगह आधा फुट तक पानी भरा हुआ है।

नगर निगम और यूआइटी की लापरवाही से शहर में कई जगह सड़कें

मूसलाधार वर्षा से भीलवाड़ा शहर के कई इलाकों में तीन-तीन फीट पानी भरा

- ग्रामीण क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में छत से टपकता पानी बिजली बोर्ड पर गिरा और दीवारों में करंट फैल गया। बच्चों को बिजली के झटके लगने लगे, प्रिंसिपल ने तुरंत कार्यवाही कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।

दुकानों और मकानों से ऊंची हो गई हैं जिस कारण मकानों और दुकानों में पानी घुसने लगा है। शहर में कई स्थानों पर तेज आंधी-तूफान के कारण करीब तीन घण्टे बिजली गुल रही जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जिले के मांडल में मानसून एक बार फिर मेहरबान हुआ है। सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी है। लगातार बारिश के कारण हाइवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भीलवाड़ा की रायला उस तहसील

के बैरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव इंदिरा कालोनी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह जैसे ही बारिश शुरू हुई तो छत टपकने लगी, इस समय विद्यालय के कमरों में बच्चे मौजूद थे। धीरे-धीरे बिजली बोर्ड पर पानी गिरा और दीवारों में करंट फैल गया। दीवारों के पास बैठे बच्चों को बिजली के झटके लगने से हो-हल्ला मच गया।

प्रिंसिपल ज्योति जांगिड़ दौड़कर आई और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और ग्रामवासियों को सूचना दी, तुरंत लाइट को बंद करवा कर अधिकारियों को सूचना दी गई। अधिकारियों ने तत्काल बिजली का कनेक्शन काट दिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

राहुल गांधी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाल रहे है।

एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो राहुल गांधी की कार्यशैली और राजनीतिक सोच से परिचित हैं, ने बताया कि इससे पार्टी में भारी अटकलों का दौर चल पड़ा है।

और भी रोचक बात यह है कि इन नेताओं का कद जितना बढ़ा है, कांग्रेस की स्थिति उतनी ही कमजोर होती गई है। “एक पद, एक व्यक्ति” का सिद्धांत राहुल गांधी के करीबी नेताओं पर लागू नहीं होता।

जैसे, कृष्णा अल्लुवेरा बिहार जैसे अहम चुनावी राज्य के प्रभावी है और साथ

ही युवा कांग्रेस के भी प्रभारी है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम लागू हो रहे है।

एक बंद दरवाजे वाली व्यवस्था बना दी गई है, जिसमें कुछ खास लोगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, भले ही उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाने में कोई ठोस योगदान न दिया हो।

भंवर जितेंद्र सिंह हर उस राज्य में असफल रहे, जहां उन्हें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार पदेनवत किया जा रहा है।

राहुल गांधी को इन सवालों के जवाब देने होंगे, खासकर उनकी कोर टीम के कई सदस्यों के प्रदर्शन को लेकर।

सरकार ने आपदा अलर्ट सिस्टम शुरू किया

नई दिल्ली, 02 जुलाई। अगर आने वाले दिनों में आपके मोबाइल में भी कोई अलर्ट का मैसेज आए, जिसमें लिखा हो कि ये एक टैस्ट मैसेज है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ये मैसेज भारत सरकार के टेलीकॉम मंत्रालय की एक तैयारी का हिस्सा है, ताकि सरकार समय रहते आम लोगों को किसी आपदा या इमर्जेंसी की सूचना लोगों तक पहुंचा सके। दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर देशभर में मोबाइल

- सिस्टम की टैस्टिंग शुरू हो गई है, सभी के मोबाइल में अलर्ट भेजा जा रहा है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

के जरिए अलर्ट सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। हाल ही, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नया इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (सचेत) शुरू किया है, जिसे सी-डीओटी ने तैयार किया है। इस सिस्टम को इंटरनेशनल टेलिकॉम यूनियन की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है। इसे देश के सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है।

यूक्रेन के लुहांस्क पर रूस का पूर्ण नियंत्रण

तीन साल तक चले युद्ध के बाद, अंततः रूस को मिली एक बड़ी सफलता

- रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम की संभावनाओं को खारिज कर दिया है।

लुहांस्क तीन साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद रूस को और भी पूरी तरह से कब्जाया गया पहला यूक्रेनी क्षेत्र बन जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व में किए गए शांति बहाली के प्रयासों के

आगे न बढ़ पाए के बीच यह बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने आ रही है। यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति बहाली की कोशिशों के लिए झटका है। इसके अलावा, इससे इस संघर्ष के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की संभावनाओं को सिरि से नकार दिया है। वे अपनी शर्तों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इन शर्तों में अवैध रूप से कब्जा किए गए

चार क्षेत्रों पर रॉस्को का नियंत्रण भी शामिल है। हालांकि, कब्जे वाले क्षेत्र के लिए रॉस्को की ओर से नियुक्त नेता लियोनिद पासचनिक के दावे पर कीव की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। सोमवार शाम को प्रसारित रूस के सरकारी टीवी चैनल वन पर बयान देते हुए पासचनिक ने कहा कि उन्हें दो दिन पहले ही एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें कहा गया था कि 100 प्रतिशत क्षेत्र अब रूसी सेना के नियंत्रण में है।

बनाए रखने की स्वतंत्रता भी दे रखी है। भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि दलाई लामा एक सम्मानित धार्मिक नेता हैं और देश की जनता उन्हें अत्यधिक सम्मान देती है।

तिब्बती जनता की निष्ठा को लेकर चीन और दलाई लामा के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं है, यह तिब्बत पर राजनीतिक नियंत्रण और वहां के लोगों की पहचान को मिटाने के प्रयास का हिस्सा भी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से हान चीनी नागरिकों को तिब्बत में बसाकर तिब्बत के मूल निवासियों की पहचान को मिटाने की मुहिम चला रही है।

इसके साथ ही, तिब्बत में अनेक बार जनविद्रोह हुए हैं, जिन्हें सीपीसी ने बेरहमी से दबा दिया है। ये विद्रोह तिब्बती जनता की असहमति और पीड़ा की अभिव्यक्ति थे। इससे पहले दलाई लामा ने कहा था कि जब वे अपने 90वें जन्मदिन के करीब होंगे, तब वे इस पद के उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया व उद्देश्य की समीक्षा करेंगे।

अब, इस रविवार को अपने 90वें जन्मदिन के अवसर पर, धर्मशाला से उन्होंने औपचारिक घोषणा की है कि अगला दलाई लामा उनकी परिषद और पारंपरिक तिब्बती धार्मिक परंपराओं के अनुसार नामित किया जाएगा।

आरएसएस व मोदी-शाह द्वय के...

- संघ परिवार भी चौंहारे पर खड़ा है और दुविधा में है। एक तरफ उस नेता के प्रति वफादारी का सवाल है, जो चुनाव की दृष्टि से सबसे सफल नेता साबित हुआ है तथा दूसरी ओर सवाल है, पार्टी में “आइडियोलॉजिकल व संगठनात्मक” संतुलन बँटाने का, 2029 के चुनाव से पहले।

संघ के भीतर यह धारणा बढ़ रही है कि भाजपा में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण, जो अब लगभग पूरी तरह मोदी-शाह तक सीमित है, ने जमीनी कार्यकर्ताओं और वैचारिक निष्ठावान लोगों को हाशिए पर धकेल दिया है। संघ के कई सदस्यों का मानना है कि हाल की राज्य स्तर की नियुक्तियों संगठनात्मक योग्यता या वैचारिक प्रतिबद्धता के बजाय केवल मोदी के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा के आधार पर की गई हैं।

यह असंतोष केवल वैचारिक नहीं है। कुछ प्रचारकों का मानना है कि आंतरिक लोकतंत्र के क्षरण और वैचारिक मूल्यों की अनदेखी ने भाजपा को कुछ प्रमुख राज्यों में चुनावी नुकसान पहुँचाया है। संघ के भीतर “नीति में सुधार” की चर्चाएं अब भीतर पकड़ने लगी हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब संगठन अपनी शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहा है, जिसे कई लोग भाजपा

के साथ संबंधों की रणनीतिक पुनर्समीक्षा के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आरएसएस और मोदी-शाह नेतृत्व इस आंतरिक संकट को कैसे संभालते हैं। भले ही खुले टकराव की संभावना कम हो, लेकिन आने वाले महीनों में संदेशों, नियुक्तियों और चुनावी रणनीतियों में बदलाव इस दिशा का संकेत दे सकते हैं।

फिलहाल, संघ परिवार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह अपने सबसे सफल चुनावी नेतृत्व के प्रति वफादारी और 2029 के आम चुनावों से पहले संगठनात्मक व वैचारिक संतुलन बहाल करने की आवश्यकता के बची फंसा हुआ है।

बांग्लादेश की पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना को 6 माह की जेल

ढाका, 02 जुलाई। निर्वासन के बाद भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अदालत की अवमानना के लिए बुधवार को छह महीने जेल की सजा सुनाई।

‘हेली स्टर’ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा

- अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायाधिकरण ने अदालत की अवमानना के आरोप में यह सज़ा सुनाई है।

मोज़मुदर की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष सोमल मीडिया पर प्रसारित हसीना से जुड़ी कथित लीक फोन बातचीत की समीक्षा करने के बाद आज यह आदेश पारित किया।

ऑडियो क्लिप में हसीना कथित तौर पर गोविंदगंज उपजिले के पूर्व

अध्यक्ष शकील अकांदा बुलबुल से कहती सुनाई दे रही है।मैंरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। न्यायाधिकरण ने इस बयान को अवमाननापूर्ण और अदालत को कमजोर करने का सीधा प्रयास माना। गैर्बांधा के गोविंदगंज से आवामी लोग

के छात्र सहयोगी प्रतिबंधित छात्र लीग के नेता बुलबुल को उनकी भूमिका के लिए दो महीने जेल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधिकरण के सूत्रों के अनुसार, सजा तभी प्रभावी होगी, जब दोषी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे या कानून प्रवर्तकों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

आरक्षित तथा 85 पद अनारक्षित होंगे। प्रत्येक रोस्टर में, आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए फ्रैक्शनल एन्टाइटलमेंट का पूरा ध्यान रखा जायेगा। उदाहरण के लिए, जूनियर कोर्ट अडिस्टेंट के पदों पर 7वां, 15वां, 20वां, 27वां पद के लिए आरक्षित है, जबकि 14वां, 28वां, 40वां पद के लिए आरक्षित किया गया है। रोस्टर के साथ ही, दस्तावेज का भाग प्रत्येक पद के लिए इनिशियल आरक्षण रजिस्टर भी प्रस्तुत करता है, जो यह दिखाता है कि किस पद पर किस श्रेणी का व्यक्ति नियुक्त हुआ है। ये रजिस्टर अद्यतन दर्तावैध के रूप में कार्य करेंगे और हर भीतरी चक्र में अपडेट किए जाएंगे।

24 जून को जारी परिपत्र सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों और

ओला, ऊबर, रेपिडो को व्यस्त समय में दोगुना किराया वसूलने की अनुमति

नयी दिल्ली, 02 जुलाई। सरकार ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी सभी कैब सेवाओं को व्यस्त समय में दोगुना किराया वसूलने की अनुमति दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 के लिए एक जुलाई को जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देशिका में इस आशय की अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकारों इसके आधार पर अपने नियम अलग बना सकती हैं और इसके लिए उन्हें तीन महीने का समय दिया गया है। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर को गैर-व्यस्त समय के दौरान बेस किराया से कम से कम 50 प्रतिशत कम चार्ज करना आवश्यक है। अब ये कैब एग्रीगेटर से पीक टाइम में बेस किराये का दोगुना तक किराया वसूल सकते हैं।